भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
17.03.2021 के
अतारांकित प्रश्न सं. 3631 का उत्तर

परियोजनाओं की लागत में वृद्धि

3631. श्री चिराग कुमार पासवान:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेलवे की कई निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी लागत में व्यापक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जोन-वार ब्यौरा क्या है और इनके पूरा होने में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) उक्त परियोजनाओं पर अब तक खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है, ताकि लागत में होने वाली और वृद्धि को रोका जा सके?

उत्तर

रेल, वाणिज्य एवं उद्योग और
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

परियोजनाओं की लागत में वृद्धि के संबंध में 17.03.2021 को लोक सभा में श्री चिराग कुमार पासवान के अतारांकित प्रश्न संख्या 3631 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (घ): 01.04.2020 तक, 53,039 किलोमीटर लंबाई की 7.5 करोड़ रु. की लागत वाली कुल 513 परियोजनाएं योजना/अनुमोदन/निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं जिनमें से 10,013 किमी लंबाई को चालू कर दिया गया है और मार्च, 2020 तक 1.86 करोड़ रु. का व्यय किया गया है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) 21,343 किमी कुल लंबाई और 4,04,853 करोड़ रु. की लागत वाली 189 नई लाइन परियोजनाएं, जिनमें से 2,633 किमी लंबाई को चालू कर दिया गया है और मार्च, 2020 तक 94,575 करोड़ रु. का व्यय किया गया है।

(ii) 7,003 किमी कुल लंबाई और 59,699 करोड़ रु. की लागत वाली 54 आमान परिवर्तन परियोजनाएं, जिनमें से 3,733 किमी लंबाई को चालू कर दिया गया है और मार्च, 2020 तक 23,405 करोड़ रु. का व्यय किया गया है।

(iii) 24,693 किमी कुल लंबाई और 2,85,324 करोड़ रु. की लागत वाली 270 दोहरीकरण परियोजनाएं, जिनमें से 3,647 किमी लंबाई को चालू कर दिया गया है और मार्च, 2020 तक 67,816 करोड़ रु. का व्यय किया गया है।

लागत, व्यय और परिव्यय सहित परियोजना-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट अर्थात् www.indianrailways.gov.in >Ministry of Railways >Railway Board >About Indian Railways >Railway Board Directorates >Finance (Budget)>Pink book (year) Railway-wise Works Machinery & Rolling Stock Programme(RSP) पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है।

किसी रेल परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के प्राधिकारियों द्वारा वन संबंधी मंजूरी, बाधक जनोपयोगी सेवाओं की शिफ्टिंग, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक स्थिति, परियोजना साइट के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परियोजना विशेष की साइट के लिए उस वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है और ये सभी कारक परियोजना के समापन समय और परियोजनाओं की लागत को प्रभावित करते हैं।

रेल परियोजनाओं के प्रभावी और त्वरित कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न उपायों में निम्नलिखित शामिल है (i) परियोजनाओं की प्राथमिकता (ii) प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के लिए धनराशि के आबंटन में पर्याप्त बढ़ोतरी (iii) फील्ड स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन (iv) विभिन्न स्तरों पर परियोजना की प्रगति की बारीकी से निगरानी (v) शीघ्र भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है और वन्यजीव मंजूरी और परियोजनाओं से संबंधित अन्य मुद्दों को हल करने के लिए। इसके परिणामस्वरूप 2014 के बाद से परियोजनाओं के निष्पादन की गति में पर्याप्त वृद्धि हुई है। 2014-20 की अवधि के दौरान, 15,350 किमी लंबी (3,395 किमी नई लाइन, 4,401 किमी आमान परिवर्तन और 7,554 किमी दोहरीकरण) 2558 किमी प्रति वर्ष की औसत दर से शुरु कर दिया गया है जो 2009-14 के दौरान 1520 किमी प्रति वर्ष चालू करने के औसत दर की तुलना में 68% अधिक है।

*****